

आबकारी टाइम्स

केवल सदस्यों हेतु

U.S. India Biofuels Summit 2024

Ethanol For A Sustainable Future

23 April New Delhi



यूपीडीए ने किया यूएसजीसी के साथ समझौता

फीड स्टॉक के रूप में मक्के की फसल विकास में अमेरिकी संस्था करेगी मदद

उत्तर प्रदेश

सरकार ने किया ₹18660 करोड़ अधिक राजस्व अर्जित

प्रदेश में खुलेंगी 1051 नई दुकानें, चुनाव आयोग से मिली मंजूरी

आबकारी राजस्व में हुई 10 प्रतिशत की वृद्धि

औद्योगिक अल्कोहल पर न्यायालय ने किया फैसला सुरक्षित

हरियाणा

एक्साइज टैक्स में हुआ, 70 फीसदी का ईजाफा

राजस्थान

आबकारी राजस्व लक्ष्य में हुई 100 करोड़ की वृद्धि

पंजाब

हाईकोर्ट ने आबकारी नीति को रखा बरकरार



आबकारी टाइम्स

आबकारी, अल्कोहल एवं मद्य निषेध पर प्रथम हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष- 14, अंक- 8, अप्रैल 2024, पृष्ठ-44

R.N.I. - UPHIN/2010/36360, MSME No. UP-03-0008022

Postal Reg. No. - L-2/9 Reg/AD-86-2022-24

प्रबन्ध सम्पादक

पी. एस. मिश्रा

सम्पादक

राजेश कुमार चौबे

मुख्य सलाहकार

हर्षवर्धन चतुर्वेदी (पूर्व उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड)
आर.एस. तिवारी (पूर्व अपर आबकारी आयुक्त)
एस.के. गोयल (पूर्व उप आबकारी आयुक्त)
रविशंकर शुक्ला (पूर्व उप आबकारी आयुक्त)

मीडिया एडवाइजर

रतन दीक्षित (वरिष्ठ पत्रकार)

ब्यूरो चीफ

गोपाल जोशी (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब)
जे.के. रावत (एनसीआर)

व्यापार प्रबन्धक

शशि योगेश्वर, अरविन्द दुबे

ग्राफिक्स डिजाइनर

बृजेश पाण्डेय

फोटोग्राफर

जय प्रकाश - लखनऊ

सहायक

अजय कुमार

कार्यालय

485, भवानी भवन, ममफोर्डगंज
(शिवाजी पार्क के सामने), प्रयागराज-211002 (उ.प्र.)

लखनऊ कार्यालय

टी-14, नीलगिरी अपार्टमेंट, वृंदावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.)

सम्पर्क : 94537 59003, 73797 00003

फोन/फैक्स : 0532-2440267

E-mail : aabkaritimes@gmail.com

Web : www.aabkaritimes.com,

मोबाइल : 9415305911, 9335126988, 9452935729

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, पी.एस. मिश्रा द्वारा
क्यूआईएस प्रिंटर्स प्रयागराज से मुद्रित और
485 ममफोर्डगंज (शिवाजी पार्क के सामने),
प्रयागराज (यू.पी.) से प्रकाशित।



06

राजश्री ग्रुप कैटालिस्ट के साथ देगी
टेक्निकल सर्टिफिकेट



07

यूपीडीए ने किया यूएसजीसी के साथ
समझौता



35

शराब और एल्कोहल का क्या है झगड़ा
सुप्रीम कोर्ट के 9 जज क्यों कर रहे इस पर माथापच्ची?



40

वाइन और चीज पर हुआ एपेक्स का
आयोजन

आबकारी टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित सामग्री व लेख, लेखकों के निजी विचार और समाचार समूहों से हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक को उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। आबकारी टाइम्स से सम्बन्धित सभी विवाद केवल प्रयागराज स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। हमारा उद्देश्य मंदिरापान को बढ़ावा देना नहीं अपितु इसके उपयोक्ता और उत्पादनकर्ता को नये-नये समाचारों से अवगत कराना है।

यूपीडीए ने किया यूएसजीसी के साथ समझौता

फीड स्टॉक के रूप में मक्के की फसल विकास में अमेरिकी संस्था करेगी मदद

उत्तर प्रदेश देश के अर्थव्यवस्था में 16 प्रतिशत उपभोक्ता आधारित गन्ना, गेहूं, लिकर और एथेनॉल के उच्चतम उत्पादन के साथ सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य है। इसे "राष्ट्र के अन्न भंडार और असीमित अवसरों की भूमि" के रूप में जाना जाता है। राज्य में अल्कोहल उत्पादन की 350 करोड़ बल्क लीटर उत्पादन क्षमता के साथ 46 बिलियन का मदिरा आधारित राजस्व का स्रोत है। मदिरा और डिस्टिलरी उद्योग की शीर्ष निकाय यूपी डिस्टिलर्स एसोशिएशन (यूपीडीए) 1983 से इस उद्योग का प्रतिनिधित्व करती आ रही है। इस उद्योग के 15 सदस्यों के साथ यूपीडीए राज्य और केन्द्र सरकार के साथ नीति और नियामक मामलों पर उद्योग के मुद्दों को रखती है। यूपीडीए के सदस्यों द्वारा राज्य में 90 प्रतिशत पेय मदिरा का उत्पादन किया जाता है। यूपीडीए के प्रेसिडेंट एस.के. शुक्ला ने बताया कि यूएसजीसी के साथ समझौता (एमओयू) उत्तर प्रदेश में मक्के की संकर प्रजाति को बढ़ावा देने और किसानों को अमेरिका की तरह कृषि से अधिक लाभ कमाने को ध्यान में रखकर किया गया है। डीडीजीएस अनाज के विकास और मार्केटिंग का लाभ आने वाले समय में मिलेगा। यह एमओयू आने वाले समय में किसानों एवं एथेनॉल उत्पादकों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा।

यूपीडीए के सेक्रेटरी जनरल रजनीश अग्रवाल ने बताया कि उनका संगठन पिछले काफी समय से वैश्विक एथेनॉल शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही विभिन्न प्रकार के फीड स्टॉक पर काम कर रहा है। मक्का विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करने और जैव ईंधन में निवेश के लिए इनवेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में यूपीडीए सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसी क्रम में यूएस ग्रेन्स काउंसिल (यूएसजीसी) जो अमेरिकी कृषि विभाग के तहत अमेरिका की एक सर्वोच्च संस्था है, के साथ एमओयू पर साइन किये गये हैं। यूएसजीसी अमेरिकी जौ, मक्का, ज्वार और डिस्टिलरी के सूखे अनाज तथा आबकारी टाइम्स। अप्रैल-2024



एथेनॉल सहित सम्बन्धित उत्पादों के लिए निर्यात बाजार विकसित करता है। यूएसजीसी 50 से अधिक देशों और यूरोपिय संघ में काम करती है। ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास की चुनौतियों के समाधान को दृष्टिगत रखकर यूपीडीए और यूएसजीसी दोनों साथ मिलकर महत्वपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं।

श्री अग्रवाल ने बताया कि मक्का जैसे विभिन्न फीड स्टॉक्स से प्राप्त एथेनॉल न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में बल्कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने तथा

किसानों के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

यूपीडीए और यूएसजीसी ने एथेनॉल क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में समझौता किया है। इस अवसर पर अमेरिकी राजदूत एच.ई.एरिक गार्सेटी तथा यूएसजीसी के अध्यक्ष और सीईओ रेयान लीग्रेंड तथा यूपीडीए के प्रेसिडेंट एस.के. शुक्ला एवं सेक्रेटरी जनरल रजनीश अग्रवाल और रेडिको खेतान के अमर सिन्हा आदि संस्थापक सदस्य उपस्थित थे।

मीठी चरी और चुकंदर से तैयार करेंगे एथेनॉल



प्रो.डी स्वैन

केन्द्र सरकार ने साल 2025 तक एथेनॉल उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है, वह पूरा हो सके इसके लिए कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में अब पहली बार मीठी चरी और चुकंदर से एथेनॉल बनाया जाएगा। इसके लिए संस्थान ने जर्मनी की फर्म एडवांटा सीड्स से करार की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली हैं और इसी माह यह करार भी हो जाएगा। इसके बाद एडवांटा सीड्स व एनएसआई के विशेषज्ञ साथ मिलकर काम करेंगे और एथेनॉल को कैम्पस के ही नैनो डिस्टिलरी प्लांट में तैयार कराएंगे।

संस्थान के निदेशक प्रो.डी स्वैन ने ईटीवी भारत संवाददाता से बताया कि मीठी चरी की जहां 10 एकड़ में खेती कराई जाएगी वहीं, चुकंदर के लिए हमने 15 एकड़ जमीन तलाश ली है। यहां पर फसलों को तैयार करने के बाद संस्थान में ही उनकी क्रशिंग यानी कटाई कराएंगे। फिर, एथेनॉल का उत्पादन शुरू होगा। प्रो. स्वैन ने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे अहम बात है, वह यह है कि हमने नॉन फूड आइटम्स को चुना है, जिसमें मीठी चरी (स्वीट सोरगम) और एक विशेष प्रकार की चुकंदर की प्रजाति (स्वीट रूट) शामिल है। उन्होंने कहा कि जब गन्ना किसान अपने खेतों में इन फसलों की खेती करना शुरू कर देंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर इन फसलों का लाभ भी मिलेगा।